पाँचवा-स्तम्भ

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 25 , अंक 1/2024

क्यों जरूरी है पैकेट पर भी सरल और स्पष्ट लेबल

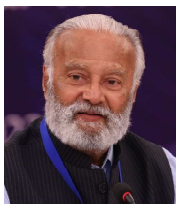

आजकल बिस्किट बहुत से लोगों के अल्पाहार का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। चूंकि बिस्किट युवा पीढ़ी के पारंपरिक भोजन की जगह तक ले रहे हैं, इसलिए उनकी पोषण सामग्री और विज्ञापन सटीकता की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है। यह जांच व्यक्तिगत स्वास्थ्य और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। बाजार के लिहाज से, भारतीय बिस्किट बाजार 4.13 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है। जिसके 2029 तक 4.078 बिलियन डॉलर के मूल्य तक पहुंचने का अनुमान है।

प्रौद्योगिकी में नवाचार और स्वस्थ विकल्पों की बढ़ती मांग जैसे कारक बिस्किट बाजार की वृद्धि में योगदान का कारण है। स्वाद, पैकेजिंग और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक विकल्प का दावा उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है। भारत में शहरीकरण ने इस बाजार को आगे बढ़ाया है। धनी व्यक्ति बिस्किट जैसे सुविधाजनक भोजन विकल्पों के लिए अधिक धन खर्च कर रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्रीय संगठन के पोषक तत्व प्रोफाइल मॉडल के अनुरूप लोकप्रिय बिस्किट ब्रांडों के तत्वों का विश्लेषण करने से चिंताजनक परिणाम सामने आए हैं। आमतौर पर सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माने जाने वाले बिस्किट ब्रांडों में से कोई भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय मानकों को पूरा नहीं करता है।

ये निष्कर्ष संभावित दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिमों को उजागर करते हैं। ये दोष विभिन्न प्रकार के बिस्किट ब्रांडों में व्यापक रूप से व्याप्त है। लगभग सभी जांचे गए बिस्किट ब्रांडों में अनुशंसित स्तर से अधिक चीनी, सोडियम और वसा सामग्री दिखाई देती है। ऐसी सामग्री का लगातार सेवन मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मोटापा और दंत समस्याओं सहित जीवन शैली से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अत्यधिक जोखिम पैदा करता है।

बिस्किटः जितने दावे किए जाते हैं, उतने फायदेमंद नहीं

केरल स्थित नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर एनसीडी के कार्यकारी निदेशक जॉनसन जे.एडयारनमुला का मानना है कि बिस्किट आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए चमत्कार नहीं करेगा। कभी-कभी और कम मात्रा में इनका सेवन किया जाता है तो ये आमतौर पर किसी के स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। माता-पिता के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि बिस्किट कभी भी उचित भोजन की जगह नहीं ले सकता हैं। और पोषण के मामले में उतने फायदेमंद नहीं है, जितने दावे किए जाते हैं। विशेष रूप से भारत में बढ़ते गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के संदर्भ में, खान-पान को लेकर उचित निर्णय लेना जरूरी है। इस बात को समझना आवश्यक है कि आहार संबंधी आदतें दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विश्व ओबेसिटी एटलस 2023 में भारत में मोटापे की बढ़ रही समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है। यह बढ़ोतरी आहार संबंधी आदतों में बदलाव लाने और पोषण विकल्प बनाने की आवश्यकता की तरफ ध्यान आकर्षित करती है।

साथ ही अत्यधिक कैलोरी सेवन और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों में योगदान करने वाले उत्पादों की खपत को सीमित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। ये निष्कर्ष और विशेषज्ञों की राय सभी पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर पैक चेतावनी लेबल के स्पष्ट और सटीक पोषण संबंधी लेबल की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। ये लेबल भाषा और साक्षरता बाधाओं को पार करने के लिए काफी सरल होने चाहिए, जिससे हर वर्ग के उपभोक्ता को स्नैक्स में मौजूद पोषण सामग्री को तुरंत समझने की अनुमति मिल सके।

चुंकि बिस्किट एक घरेलू व आम खाद्य पदार्थ बना हुआ है, इसलिए स्पष्ट लेबल लागू करने से न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा होगी, बल्कि सामुदायिक कल्याण के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप स्वस्थ आहार आदतों में बदलाव को भी बढ़ावा मिलता है।

प्रदीप एस महता
महामंत्री, कट्स इंटरनेशनल

इस अंक में...

- सरकारी में पढ़ रहे बच्चे, निजी स्कूलों..... 3
- हमारी भूमिका 'विश्व मित्र' की है..... 5
- वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा भारत 7
- शांति और समृद्धि के लिए जल है जरूरी 9
- ड्रोन से खेतों में बीज बोएंगी महिलाएं 10

जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यशाला आयोजित

बैंक उपभोक्ता धोखाधड़ी से बचने के लिए बरते सावधानी

भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से 'कट्स' मानव विकास केंद्र द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए जिला प्रबंधक अशोक कुमार देवनानी ने बैंक ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता बताई।

उन्होंने कहा कि बैंक से नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एवं वालेट्स से धनराशि निकालने व जमा कराते समय अधिक सावधानी रखनी चाहिए। जरा सी भी असावधानी बरतने पर धोखेबाज उसका फायदा उठाने में पीछे नहीं रहते। उन्होंने ऐसी स्थिति में इससे बचने के तरीके और धोखेबाजी से हुए नुकसान के लिए समय पर बैंकों को शिकायत करने और उनके समाधान के तरीकों की जानकारी देते हुए जागरूक रहने की सलाह दी। मुख्य वक्ता के रूप में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक महेन्द्र डूडी ने बचत के तरीके, आम जनता की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा के तरीके, विभिन्न प्रकार के बैंक खातों की जानकारी दी और उनके फायदे बताए। साथ ही स्मार्टफोन यूजर उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी।

इस अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ी सादड़ी के शाखा प्रबंधक दिनेश शर्मा ने ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और केवाईसी आदि की जानकारी दी। 'कट्स' के सह निदेशक दीपक सक्सेना द्वारा बैंकों के डेफ कोष और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उससे संचालित इस परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में अन्य प्रतिभागियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला का संचालन मदन गिरी गोस्वामी ने किया। कार्यशाला में स्कूली छात्र-छात्राओं, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं किसान उत्पादक संगठनों के सदस्यों सहित 66 लोगों ने भाग लिया।

बृजमोहन आचार्य 'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित

'कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष उन श्रेष्ठ पत्रकारों को दिये जाते रहे हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मामलों को असरदार तरीके से उठाया है। इस बार वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार 'कट्स' द्वारा 'भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम' के तहत जोधपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय मंडोर में आयोजित कार्यशाला के दौरान मुख्य अतिथि, कुलपति बी.आर. चौधरी द्वारा बीकानेर जिले के पत्रकार बृजमोहन आचार्य को प्रशस्ति पत्र एवं 10 हजार रुपए का चैक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

श्री आचार्य प्रतिष्ठित हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के बीकानेर संस्करण से जुड़े हैं। उन्होंने वर्ष 2022 के दौरान 'राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं कितनी लाभकारी' विषय पर कई रोचक स्टोरियां प्रकाशित कर आमजन में जागरूकता लाने एवं जनचेतना जागृत करने का काम किया है।

सरकारी में पढ़ रहे बच्चे, निजी स्कूलों ने उठाया भुगतान

प्रदेश में करीब 16 हजार विद्यार्थियों का निजी एवं सरकारी स्कूलों में दोहरा नामांकन मिला। ये बच्चे शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों के साथ सरकारी स्कूलों में भी पंजीकृत हैं। अधिकारियों को ऐसे हालात प्रदेश के हर जिले में सामने आए हैं।

आरटीई के तहत फर्जी प्रवेश रोकने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से पोर्टल पर निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की जानकारी ली गई थी। पोर्टल पर विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, विद्यार्थी की जन्मतिथि के साथ आधार संख्या भरवाई गई। आधार कार्ड से मिलान करने पर यह गड़बड़झाला सामने आया। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले जिन बच्चों का दोहरा नामांकन मिला उन्हें आटीई के तहत दी जाने वाली पुनर्भरण राशि रोक दी गई है। अब सत्यापन के बाद स्थिति स्पष्ट होने पर ही उनको भुगतान किया जाएगा। नामांकन दोहरा मिलता है तो पुनर्भरण की अब तक भुगतान की गई राशि को वापस वसूला जाएगा। *(रा.प., 20.03.24)*

भ्रष्टों के खिलाफ कब होगी सख्ती

प्रदेश में पेपरलीक और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में सख्त दिख रही भजनलाल सरकार अब भ्रष्ट नौकरशाहों की जांच को लेकर 45 विभागों में लंबित चल रही 469 अभियोजन स्वीकृति के मामलों में कठोर कदम उठाएगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी संख्या में नौकरशाहों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है।

यह भ्रष्टाचार के मामले एक दशक से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। इनके खिलाफ जांच के लिए एसीबी को अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब चर्चा है कि सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति के चलते मुख्यमंत्री जांच के लिए विभागों से अभियोजन स्वीकृति दिलवा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि कार्मिक विभाग में भी करीब 54 मामलों में अभी तक अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है। अब यह विभाग मुख्यमंत्री के पास है। *(रा.प., 12.01.24)*

'उड़ान' योजना में नहीं मिल रहे 'नेपकिन'

प्रदेश में उड़ान योजना के तहत 18 से 45 आयुवर्ग की बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क बांटने के लिए सेनेटरी नैपकीन (पैड) नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी बालिका स्कूलों को पैड की आपूर्ति नहीं हो रही है। इससे 26 लाख स्कूली छात्राएं और 3 लाख ग्रामीण महिलाएं परेशान हैं।

गौरतलब है कि हर महीने प्रत्येक छात्रा और महिलाओं को 12 नैपकिन का सेट दिया जाता था। नाबार्ड ने अपनी 'माई पैड-माई राइट' योजना के तहत प्रदेश में पैड बनाने की तीन यूनिट लगाने के लिए वित्तीय मदद की थी। लेकिन अब मशीनों पर पैड बनाने का काम ठप्प पड़ा है। जैसलमेर में भी एक यूनिट दिसंबर में शुरू होनी थी लेकिन उत्पादन शुरू ही नहीं हो पाया। यूनिट्स को स्वयं सहायता समूह ही संचालित कर रहे हैं। पैड की आपूर्ति बंद होने से पांच सौ महिलाओं का रोजगार भी चला गया।

(रा.प., 24.03.24)

दुनिया से ज्यादा भारत में असमानता

भारत में अब अमीरों और गरीबों के बीच अंग्रेजों के राज से भी ज्यादा असमानता का दौर है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब (विश्व असमानता रिपोर्ट) के मुताबिक 2022-23 में देश की सबसे अमीर 1 प्रतिशत आबादी की आय में हिस्सेदारी बढ़कर 22.6 प्रतिशत हो गई है। वहीं संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 40.1 प्रतिशत हो गई है।

ऐसा सौ साल में पहली बार हुआ है। भारत में आमदनी और संपत्ति मेंअसमानता, '1922-23: अरबपति राज का उदय' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार असमानता की खाई 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद बढ़ी है। लेकिन पिछले एक दशक में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। देश में एक फीसदी अमीरों के पास आय-संपत्ति में हिस्सेदारी दुनिया के प्रमुख देशों में सबसे अधिक है। वर्ष 2015 से 2023 में टॉप एक फीसदी अमीरों में संपत्ति का जमावड़ा बेहद ज्यादा हो गया है। रिपोर्ट में आय और संपत्ति पर टैक्स ढांचे को दुरुस्त करने की बात भी कही गई है।

(दै.भा., 21.03.24)

गहलोत सरकार छोड़ गई कर्जे का भार

प्रदेश की आर्थिक सेहत को पटरी पर लाना भजनलाल सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पिछली कांग्रेस सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में पिछले साल के मुकाबले 61 प्रतिशत ज्यादा कर्ज लिया है। इसमें से सबसे ज्यादा 44 हजार 736 करोड़ रुपए की उधारी जुलाई माह के बाद ली गई है।

इस दौरान प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए योजनाओं के नाम पर जनता के लिए खजाना खोल दिया गया था। मुफ्त की घोषणाओं के चलते प्रदेश की आर्थिक सेहत बिगड़ गई। कर्ज के लिहाज से राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं थी। वर्ष 2022-23 में अनुमानित कर्ज 5,16,815 करोड़ रुपए था। अब माना जा रहा है कि मार्च 2024 के अंत तक यह कर्ज 5,79,781 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। *(रा.प., 02.01.24)*

कहां गई हरियाली, पौधे कहां बंटे?

प्रदेश में कांग्रेस की 'घर-घर औषधी योजना' सवालों के घेरे में आ चुकी है। वनमंत्री संजय शर्मा ने विभाग की पहली बैठक में इस योजना की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत घर-घर औषधि के पौधे बांटे जाने थे। मंत्री ने बैठक में कहा पौधे कहां बंटे? मेरे घर तो नहीं आए। कई अफसरों ने भी हामी भरी हमारे घर भी नहीं पहुंचे।

इस पर मंत्री ने पूरा ब्योरा मांगा है और जांच कराने को कहा है। उन्होंने ग्राम सुरक्षा वन समितियों के जरिए हो रही गड़बड़ी पर भी सवाल उठाए और उनके गठन, चुनाव आदि को लेकर भी जानकारी मांगी। गौरतलब यह है कि 208 करोड़ रुपए की योजना चार साल के लिए बनी, पर डेढ़ साल ही चली। हर साल 52 करोड़ रुपए खर्च होने थे। योजना को लेकर एजी ने भी सवाल उठाए है। *(दै.भा., 03.02.24)*

बिना जानकारी बंटा करोड़ों का गेहूं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जयपुर जिले में लाभ ले रहे करीब 54 हजार 722 लोगों का जनाधार से मैपिंग नहीं है। इसके बावजूद राशन की दुकानों से एक साल में 5.91 करोड़ रुपए का करीब 32 लाख 83 हजार 320 किलो राशन का गेहूं वितरण हो गया।

जन आधार की राशन कार्ड से मैपिंग नहीं होने से पता नहीं चल पा रहा कि है कि राशन कार्ड से जुड़े लाभार्थी जीवित है या नहीं, युवतियों की शादियां हो गई या नहीं, क्या लोगों ने अपने क्षेत्र बदल लिए। अब राशन का गेहूं किन लोगों द्वारा उपयोग में लिया गया इसकी जानकारी नहीं है। जिले में कुल 619979 राशन कार्ड में 54722 सदस्य जनाधार से मैप नहीं है। अब जाकर उचित मूल्य की दुकानों पर जन आधार से मैपिंग होगी।

(दै.भा., 08.01.24)

गोशालाओं के नाम पर बड़ा घोटाला

गोशालाओं के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। कई गोशालाओं में ऑनलाइन 215 से 641 गायें बताकर पैसा उठाया गया। जांच में वहां न गाय मिली, न चारा-गोबर-पानी। यानी इन कागजी गोशालाओं ने सरकार को मोटा चूना लगाया। गोपालन निदेशालय ने जैसलमेर टीम भेजकर 12 गोशालाओं की जांच कराई और अनुदान रोक दिया है।

इसकी गोपनीय रिपोर्ट सरकार व जैसलमेर कलेक्टर को भेज दी गई है। दो साल में 51.23 करोड़ रुपए उठा चुकी 12 गोशालाओं में 7129 गायें बता रखी थीं। जिला स्तरीय कमेटी ने 6582 गोवंश बताया था, लेकिन जांच में 310 गायें ही मिली। किसी भी गोशाला में 100 गायें भी नहीं मिली। मेहर गोशाला में 215 गायें बताई, जांच में कमेटी को यहां गाय, चारा, पानी कुछ नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक जैसलमेर जिले में पशुपालन विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता से यह सब हुआ है। *(दै.भा., 01.03.24)*

अपात्र किसानों ने उठाया बेजा लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कई अपात्र किसानों ने बेजा लाभ उठा लिया। अब तक की गई जांच में प्रदेश में 16.76 लाख किसानों को इस योजना के तहत अपात्र माना गया है। इसमें से करीब 13 लाख किसानों के नाम पोर्टल से हटा दिए हैं। शेष 3.80 लाख किसानों की जांच प्रक्रियाधीन है।

योजना में किसान सम्मान निधि पाने के पात्र है या नहीं, इसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की है। इसमें प्रदेश स्तर, जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर अलग-अलग कमेटियां जांच कर रही है। इसमें जिन किसानों ने आवेदन किया है, उनके दस्तावेजों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। *(रा.प., 18.02.24)*

दवा निःशुल्क है, पता नहीं उनका मोल

प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में दवा काउंटरों पर मरीजों को भले ही दवाइयां निःशुल्क दी जाती हो। भले ही राज्य सरकार इन दवाओं की खरीद के साथ मरीजों तक पहुंचाने की आपूर्ति चेन पर भी भारी खर्चा करती हो, लेकिन मरीजों या उनके परिवारजनों के पास बिना उपयोग की गई बड़ी मात्रा में दवाएं बेकार पड़ी रहती है।

ऐसी दवाओं को वापस दवा काउंटरों तक मंगवाने का मजबूत सिस्टम अब तक नहीं बन पाया। वहीं मरीज और उनके परिजन भी इन दवाओं को लौटाने का प्रयास नहीं करते। जानकारी के मुताबिक दवा योजना की शुरुआत के साथ ही दवा लौटाने के लिए सरकारी अस्पतालों में ड्रॉप बॉक्स लगाने की व्यवस्था थीं। अब ये बॉक्स अस्पतालों में कहां है किसी को पता नहीं है। लोगों में जागरूकता पैदा कर करोड़ों रुपए की इन दवाओं का पुनः इस्तेमाल हो सकता है। *(रा.प., 04.01.24)*

लिंग जांच कानून तोड़ने में हम आगे

जहां एक तरफ प्रदेश में लिंगानुपात तेजी से सुधर रहा है वहीं लिंग जांच बेधड़क जारी है। तमाम जागरूकता और कानून के बावजूद कोख में कत्ल नहीं थम रहे। प्रसव पूर्व लिंग जांच रोकथाम के लिए बने कानून पीसीपीएनडीटी के उल्लंघन के सर्वाधिक मामले भी राजस्थान में सामने आए हैं।

पिछले तीन साल में इस अधिनियम के तहत देश में दर्ज कुल अदालती मामलों में से 26 फीसदी राजस्थान के हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट मरुधरा के माथे पर कलंक लगा रही है। इस अधिनियम के तहत पिछले तीन सालों में देश में कुल 615 अदालती मामले दर्ज हुए उनमें से 158 राजस्थान के हैं। हरियाणा 96 मामलों के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 95 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। *(रा.प., 16.02.24)*

अफसर ले गए फायदा... कर्ज में डूबे जरूरतमंद?

प्रदेश में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना सिर्फ अफसरों की बनकर रह गई। विदेश में पढ़ाई कराने का सपना दिखाकर कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2021 में जरूरतमंदों के लिए योजना शुरू की थी। लेकिन योजना का दायरा बढ़ाकर अधिकारियों ने अपने बच्चों को सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ाई कराने की व्यवस्था कर ली।

गौरतलब है कि यह योजना 200 छात्रों के लिए शुरू हुई जिसमें न्यूनतम आठ लाख आय वर्ग वाले छात्रों को शामिल किया जाना था। प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण योजना में आवेदन नहीं आए। इसके बाद 25 और 50 लाख रुपए आय वर्ग वाले छात्रों को शामिल किया गया। इसका फायदा उठाकर प्रदेश के 14 आईएएस, आईपीएस सहित 73 अफसरों ने अपने बच्चों को सरकारी खर्च पर विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। अब 2023 में योजना का बजट गड़बड़ा गया है। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के अभिभावकों को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलने से कर्ज लेना पड़ रहा है। *(रा.प., 04.02.24)*

नवाचार दिखाएंगे विकास का रास्ता

सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने की दिशा में तेजी लाने को लेकर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि विकास लक्ष्यों की स्थिति में निचले स्तर तक सुधार लाने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में काफी नवाचार हो रहे हैं। यह सम्मेलन इन नवाचारों को आपस में साझा कर उनका लाभ देश भर में पहुंचाने का माध्यम बनेगा।

सम्मेलन में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के.पाल ने कहा कि एसडीजी को लेकर किए जा रहे प्रयासों को लगातार आगे बढ़ाना होगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि एसडीजी को पूरा करने के लिए की जा रही प्रगति में तेजी लाना महत्वपूर्ण कदम है। नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योगेश सूरी ने कहा कि एसडीजी की सफलता के लिए भारत दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाएगा। संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक शोम्बी शार्प ने प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए नीति आयोग के प्रयासों की सराहना की। *(रा.प., 05.03.24)*

शिक्षा में नवाचार व अनुसंधान पर जोर

भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नवाचार, अनुसंधान, रिसर्च, और ग्रीन एक्टिविटीज की दिशा में काम करना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने से अब राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ने इसी के अनुरूप शिक्षण संस्थानों के काम का मूल्यांकन करने के पैरामीटर तय किए हैं।

नई व्यवस्था के तहत नैक अब पहले की तरह ग्रेडिंग नहीं देगी। इसकी जगह शिक्षण संस्थानों के लेवल तय किए जाएंगे। टॉप संस्थानों को सेंटर फॉर एक्सीलेंस का दर्जा मिलेगा। नई प्रक्रिया को इसी साल दिसंबर तक लागू कर दिया जाएगा। नैक विशेषज्ञ डॉ.दिव्या जोशी के अनुसार अभी कॉलेजों या विश्वविद्यालयों को साल में एक बार एक्यूएआर की रिपोर्ट एवं पांच साल में एक बार एसएसआर की रिपोर्ट देनी होती है। नई प्रक्रिया में रोजाना या साप्ताहिक रूप से डेटा प्रबंधन के साथ-साथ टीचिंग व लर्निंग का डेटा भी सार्वजनिक करना होगा।

(रा.प., 19.02.24)

विकास के साथ रखें प्रकृति का ध्यान

हर नागरिक अपना कर्तव्य पूरा कर किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे जो आत्म अनुभूति होगी वही हमारा सच्चा पुरस्कार है। विकास के साथ प्रथ्वी और प्रकृति का भी खयाल रखना होगा। वृक्ष, नदी, पर्वत और जीव-जन्तुओं से रिश्ता बनाकर इनका संरक्षण करना होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में यह बात रखी। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमें मानव विकास के लिए पर्यावरण व प्रकृति के साथ सामंजस्य व संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। राज्य सरकार पं.दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए कार्य कर रही है। *(रा.प., 06.03.24)*

पर्यावरण के लिए रेलवे का कायाकल्प

पर्यावरणीय हितों, स्वास्थ्य, सुरक्षा और तेजी से विकास को ध्यान में रखते हुए भारत में रेलवे का कायाकल्प अभियान शुरू हो चुका है। राजस्थान समेत देशभर में 41 हजार करोड़ की दो हजार से अधिक परियोजनाओं पर काम हो रहा है।

खाड़ी देशों में भी अब जलवायु परिवर्तन रोकने और शहरों के फासले कम करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इन देशों में परिवहन के लिए इस विश्वसनीय, टिकाऊ और अपेक्षाकृत सस्ते साधन की वकालत की जा रही है। जैसे-जैसे यह क्षेत्र जलवायु बदलावों को लेकर कोप28 के परिणामों को समझ रहे हैं, नए परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रहा है। इनका लक्ष्य अपने देशों के भीतर 2000 किमी से अधिक लंबा ट्रैक बिछाना है। यूरोप में भी यह साल ट्रेनों के लिए शानदार रहने वाला है।

(रा.प., 02.01.24, 27.02.24)

देश में गरीबी खत्म होने के कगार पर

भारत में अत्यधिक गरीबी खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। इसका खुलासा 'द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक' की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में अब 3.5 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी की सीमा में बचे हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक है।

माना गया है कि सरकार की नीतियां कारगर होने से गरीबी घट रही है। इससे पहले नीति आयोग भी कह चुका है कि देश में अत्यधिक गरीबी में तेजी से गिरावट आई है। वर्ष 2013-14 में अत्यधिक गरीबों की संख्या 29.17 प्रतिशत थी, जो 2022-23 में घटकर मात्र 11.28 प्रतिशत रह गई है। इन 9 साल में 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी भारत में गरीबी कम होने की बात कही गई है। *(रा.प., 03.03.24)*

हमारी भूमिका 'विश्व मित्र' की है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में 10वीं 'वाइब्रेंट गुजरात समिट' का उद्घाटन करते हुए कहा कि तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में भारत 'विश्व मित्र' के रूप में बढ़ रहा है। सभी रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि भारत कुछ वर्षों में तीन सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्थाओं में से एक होगा।

उन्होंने कहा कि दुनिया, भारत को स्थिरता के एक महत्वपूर्ण स्तंभ और वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के इंजन के रूप में देखती है। हमने अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। समिट में 4 राष्ट्राध्यक्ष, 130 देशों के मंत्री-गवर्नर समेत उद्यमी शामिल हुए। समिट में भारत के प्रमुख उद्योगपतियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा किए जाने वाले निवेश तथा उससे होने वाले विकास, उत्पादन व रोजगार आदि से संबंधित ब्योरा पेश किया।

(दै.भा., 11.01.24)

अंतरिम बजट पर एक नजर

लोकसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनावों से पूर्व अंतरिम बजट 2024 प्रस्तुत किया। वहीं राजस्थान विधानसभा में वित्तमंत्री दिया कुमारी ने भी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल अंतरिम बजट (लेखानुदान) रखा है। अंतरिम बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अच्छे प्रावधान रखे गए हैं।

खुशियों से भरेंगे किसानों की झोली

केंद्रीय अंतरिम बजट में वित्तमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया है कि अन्नदाताओं की जरूरतों, उनकी आकांक्षाओं और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें वर्तमान में जारी सभी योजनाओं के लाभ प्राप्त होते रहेंगे। फसल कटाई के बाद स्टोरेज के लिए प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो सकेगा। कृषि सिंचाई के लिए बजट में 22 फीसदी तक वृद्धि की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और दस लाख रोजगार पैदा हुए हैं।

राजस्थान के अंतरिम बजट में 2000 करोड़ रुपए का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाने, किसानों को मोटे अनाज (श्रीअन्न) को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता के बीज किट देने, किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर 5 लाख गोपालक परिवारों को गोपाल क्रेडिट कार्ड देने तथा पीएम सम्मान निधि के तहत सालाना 8000 रुपए आर्थिक मदद देने के लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान एग्रीकल्चर इन्फ्रा मिशन-2 में 2 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 20 हजार फार्म पॉण्ड, 10 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी, 5 हजार वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां एवं नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड पार्क तथा होर्टिकल्चर हब बनाए जाने का वादा अंतरिम बजट में किया गया है। हर किसान को एक लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण मिलेगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

नब्ज पर हाथ, सेहत का रखा ख्याल

केंद्र के बजट में लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए वर्तमान में दी जा रही सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने और जरूरतमंदों के लिए ज्यादा लाभदायक बनाने की बात की गई है। चुनावी साल होने से लोक लुभावनी घोषणाएं न करके योजनाओं के लिए फंड की घोषणा जुलाई में पेश होने वाले बजट में किए जाने की बात विवेकपूर्ण मानी जा रही है। 9-14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीके लगाने की योजना सराहनीय कदम है।

राज्य के अंतरिम बजट में वित्तमंत्री द्वारा जनस्वास्थ्य को लेकर कई घोषणाएं की गई है। आम जन को गंभीर बीमारी पर और ज्यादा राहत देने के मकसद से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आइपीडी के साथ-साथ डे-केयर पैकेज जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए दो किश्तों में 5 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर प्रथम चरण में 6 हजार 500 रुपए किया जा रहा है। इस योजना पर 90 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान बजट में रखा गया है। 250 करोड़ रुपए से प्रदेश में अगले साल आयुष कार्यक्रम चलाये जाएंगे। मौजूदा सुविधाओं का उपयोग कर नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इससे सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को बचाने में मदद मिल सकेगी।

महिलाएं बनेंगी 'लखपति दीदी'

केंद्रीय बजट में महिलाओं के आर्थिक विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई घोषणाएं हैं। नए संसद भवन के पहले सत्र में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को आगे लाने से अनेक सुविधाएं मिलेंगी। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत वित्तीय मदद बढ़ेगी। इसके जरिए 5 साल में 3 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तमंत्री ने बताया कि अबतक करीब एक करोड़ महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में 14 लाख आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को जोड़ा जाएगा।

विकसित राजस्थान का संकल्प लेते हुए वित्तमंत्री ने प्रदेश के अंतरिम बजट में 'लखपति दीदी' योजना के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 5 लाख परिवारों की आय एक लाख रुपए वार्षिक तक पहुंचाने का वादा किया है। महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले ऋण से उद्यमिकता बढ़ेगी। मानदेय कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी से आंगनबाड़ी कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। प्रदेश के हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वॉयड और सार्वजनिक स्थलों, महिला छात्रावासों में व नारी निकेतनों में सीसीटीवी केमरे लगेंगे, इससे महिलाओं की सुरक्षा को बल मिलेगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बालिका जन्म पर एक लाख रुपए सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा।

बुनियादी ढांचा विकास पर फोकस

केंद्रीय अंतरिम बजट में चहुंमुखी विकास के लिए बुनियादी ढांचा विकास पर ज्यादा जोर देते हुए पूंजीगत व्यय 11.1% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। मोदी सरकार का खास फोकस गरीबों लिए घर पर ज्यादा है। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन 54,103 लाख करोड़ से बढ़कर 80,671 करोड़ रुपए किया गया। शहरों में मेट्रो, रेलवे, हवाई अड्डे, सडकों व मेडिकल कॉलेज आदि का विस्तार होगा। साथ ही बिजली, पानी और ग्रामीण विकास जैसी अन्य योजनाओं का विस्तार होगा। मनरेगा का बजट 43% बढ़कर 86 हजार करोड़ रुपए किया गया है।

इधर राजस्थान के बजट में पर्यटन और आधारभूत ढांचें की मजबूती के लिए अच्छे प्रावधान किए गए हैं। वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए तेजी से आवास बनाने, जयपुर मेट्रो का विस्तार करने, जयपुर के पास हाईटेक सिटी विकसित करने, चार शहरों में इनोवेशन स्टूडियों बनाने, मेडिकल कॉलेज खोलने, मंदिरों व पर्यटन स्थलों के विकास करने व गांवों में 5 लाख जल संरचनाए बनाने जैसे कई बड़े कदम बढ़ाए हैं।

वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा भारत

केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट से पहले आर्थिक सर्वे के बदले 'द इंडियन इकोनोमीः ए रिव्यू' रिपोर्ट जारी की है। इस 'मिनी आर्थिक सर्वे' यानी समीक्षा रिपोर्ट में देश की आर्थिक-सामाजिक सेहत का खाका खींचा गया है।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि तीन साल में यानी 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए 5 ट्रिलियन डॉलर को पार कर लेगी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वहीं वर्ष 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है। सुधारों के जारी रहने से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। समीक्षा में कहा गया है कि ग्लोबल चुनौती पर नजर रखते हुए भारत सहित विकासशील देशों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कामगारों के स्किल को बढ़ाने पर फोकस रखना चाहिए।

(रा.प., 30.01.24)

राज्यों के विकास को लगेंगे पंख

देश की अर्थव्यवस्था में उछाल और ज्यादा कर संग्रहण होने से केंद्र सरकार की ओर से राज्यों में धनवर्षा होने वाली है। राज्यों को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में केंद्र से अगले साल 1.15 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलने का अनुमान है। साथ ही मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी पहले से अनुमानित राशि से 83 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि राज्यों को दी जाएगी।

केंद्र से ज्यादा राशि मिलने से राज्यों के विकास को पंख लगेंगे और विकास योजना व जन कल्याणकारी उपायों में वृद्धि के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने की भी पूरी उम्मीद है। अक्सर विपक्षी दलों की सरकारें केंद्र की मोदी सरकार पर राजनीतिक भेदभाव के चलते राशि रोकने का आरोप लगाती रही हैं। हकीकत यह है कि केंद्र में ज्यादा कर संग्रहण का लाभ सभी राज्यों को मिलता है और एकत्र राशि वित्त आयोग के फॉर्मूले के तहत राज्यों को नियमानुसार वितरित की जाती है। *(रा.प., 05.02.24)*

योजनाओं के लिए नहीं धन की कमी

राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में केंद्र से रिलीव होकर आए आईएएस अफसर सुधांश पंत ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। केंद्र और राज्य का निश्चित रूप से अच्छा समन्वय रहेगा।

उन्होंने कहा राज्य को केंद्र सरकार का सहयोग मिलता रहेगा। मैं नहीं समझता किसी तरह की कोई परेशानी आएगी, बल्कि केंद्र को खुशी होगी यदि हम अपनी राशि समय पर खर्च कर सकें। जो भी केंद्र सरकार से मांग की जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि वह मिलेगी। प्रदेश हित में जो भी निर्णय होंगे, उनको लिया जाएगा। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए जो भी कदम होंगे उठाए जाएंगे। आम नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। *(दै.भा., 02.01.24)*

सरकार लेगी पाई-पाई का हिसाब

केंद्र सरकार की राजस्थान में चल रही ग्रामीण विकास की हजारों करोड़ों रुपए की केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं के खर्चे पर पूरी निगाह रहेगी। सरकार एक-एक पैसे का हिसाब लेगी। इसके लिए राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी होगी।

ग्रामीण विकास की जिन योजनाओं के लिए निर्देश दिए है उनमें मनरेगा सबसे बड़ी केंद्रीय प्रवर्तित योजना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी कई योजनाएं भी है।

इन योजनाओं में सरकारी पैसे का दुरुपयोग होने के अक्सर मामले सामने आते हैं। अब इस पर राज्य सरकार को पूरा नियंत्रण रखना होगा। राज्य सरकार इन योजनाओं के खर्चे की जांच, आंतरिक ऑडिट और मॉनिटरिंग कराएगी। इसके लिए 240 अफसरों का पूल बनाएगी, जो योजनाओं के खर्च की पूरी जांच करेंगे। राज्य सरकार की ओर से इन अफसरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी।

(रा.प., 13.02.24)

सही दिशा में आगे बढ़ रहा देश

भारत के लोग दुनिया में भविष्य के प्रति आशावादी लोगों में से हैं। अहम बात यह है कि भारत में यह आशावाद दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ा है। इस बात का खुलासा इप्सोस के फरवरी 2024 में किए गए सर्वेक्षण से होता है। भारत में 78 फीसदी लोग मानते हैं कि देश सही दिशा में जा रहा है।

गौर करने की बात है कि हालात के बेहतर होने के प्रति आशावादी रवैया ग्लोबल साउथ के देशों में विकसित-पश्चिमी देशों से ज्यादा है। सर्वे में शामिल 29 देशों में भारत समेत सिर्फ 8 देश ऐसे हैं, जहां हालात बेहतर मानने वालों की संख्या, हालात बदतर हो रहे मानने वालों की संख्या से ज्यादा है। सर्वे के अनुसार भारतीय लोग सबसे अधिक महंगाई और बेरोजगारी के प्रति चिंतित दिखे। लेकिन भारत में सबसे तेजी से सकारात्मकता बढ़ रही है। इससे पहले सितंबर 2023 में जारी गैलप के सर्वे में भी भारत में 85 फीसदी लोगों ने माना था कि उनके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है। *(रा.प., 20.03.24)*

भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए खतरा

सुप्रीम कोर्ट ने 'वोट के बदले नोट' मामले में अहम फैसला सुनाया है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि सांसद और विधायक रिश्वत के मामले में मुकदमें में छूट नहीं पा सकते। अगर वे संसद और विधानसभाओं में अपने भाषणों या वोट के बदले रिश्वत लेते हैं तो उन पर मुकदमा चलना चाहिए।

संविधान पीठ ने कहा कि ऐसे आपराधिक मामले में उन्हें विशेषाधिकार के तहत कोई कानूनी संरक्षण हासिल नहीं होगा। ईमानदारी से काम की आजादी है, भ्रष्टाचार करने की नहीं। अगर सांसद या विधायक सदन में वोट देने या सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेते हैं तो यह लोकतंत्र पर प्रहार है। इस फैसले ने दलों को एक ऐसा हथियार दे दिया है जो धोखा देने और बागी बनने वाले सदस्यों को सबक सिखाने में मदद करेगा।

(रा.प. एवं दै.भा., 05.03.24)

बिजली में प्रदेश बनेगा आत्मनिर्भर

प्रदेश को बिजली संकट से उबारने के लिए भजनलाल सरकार ने कवायद शुरू की है। ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए अब 1.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम की मौजूदगी में थर्मल और अक्षय ऊर्जा उत्पादन के नए प्रोजेक्ट के लिए विद्युत निगमों और केंद्रीय उपक्रमों के बीच पांच एमओयू और एक पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

माना जा रहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में इतना बड़ा निवेश होने के बाद राजस्थान बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा और बाहर से बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कुप्रबंधन से प्रदेश में बिजली संकट गहराया।

(रा.प. एवं दै.भा., 11.03.24)

घरों की छत पर लगेंगे सोलर पैनल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित सर्वोदय योजना के पहले चरण में राजस्थान के तीन जिले जयपुर, जोधपुर व सीकर को चिन्हित किया गया है। योजना के तहत गरीब या मध्य वर्ग के घरों की छत पर फ्री में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इन जिलों में तीन हजार रूफटॉप सोलर कनेक्शन दिए जाएंगे।

डिस्कॉम के अधिकारियों ने योजना को मूर्तरूप देने की तैयारी शुरू कर दी है। योजना के अनुसार जयपुर, जोधपुर और सीकर में एक-एक हजार नए रूफटॉप सोलर कनेक्शन लगाए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार ने भी रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए कई नए प्रावधान किए हैं। गौरतलब है, इस योजना के तहत देशभर में एक करोड़ रूफटॉप सोलर कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

(दै.भा., 01.02.24)

विद्युत वितरण तंत्र में होगा सुधार

सस्ती बिजली उत्पादन (सौर ऊर्जा) को बढ़ावा देकर किसानों को दिन में ही बिजली आपूर्ति करने और विद्युत वितरण तंत्र में सुधार के लिए राजस्थान अब महाराष्ट्र मॉडल अपनाएगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में मुलाकात की।

इस दौरान सस्ती बिजली उत्पादन के मॉडल को लेकर लंबी चर्चा हुई। महाराष्ट्र में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अब तक परंपरागत ऊर्जा के स्त्रोतों से चल रहे सिंचाई पंपों को सोलर पंपों में बदला जा रहा है। सौर ऊर्जा संचालित पंपों का उपयोग बढ़ाने की महाराष्ट्र सरकार की इस मुहिम से किसानों को सिंचाई कार्य के लिए दिन में भी सस्ती बिजली मिल रही है। इतना ही नहीं किसान सोलर पैनल के माध्यम से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को सरकारी या निजी कंपनी को बेचकर लाभ भी कमा रहे हैं।

(रा.प., 29.01.24)

प्रदेश में होगा सोलर प्लेट का निर्माण

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बाद रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए बूम आने वाला है। सोलर सेल और मॉड्यूलर यानी सौर ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र निर्माण में राजस्थान अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। यहां पर सोलर मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों ने व्यापक स्तर पर प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान को सार्थक करने के लिए राजस्थान में कंपनियां सूचीबद्ध हो रही हैं। जयपुर के पास दो प्लांट शुरु भी हो चुके हैं। सोलर मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए 6 कंपनियों ने सरकार के पास आवेदन किया है। राजस्थान में 23 हजार मेगावॉट की सोलर प्लेट बनेंगी। इन कंपनियों से पहले फेज में करीब 4400 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है।

(दै.भा., 04.02.24)

सौर ऊर्जा में बढ़ रहा विदेशी निवेश

हमारी धरा पर सिंगापुर और यूके सूरज से अपनी किस्मत चमका रहे हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर कई देश इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। पिछले तीन साल में ही सोलर में 32000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश हुआ है। इस क्षेत्र में सिंगापुर और यूके ने हमारे यहां सबसे ज्यादा निवेश किया है।

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में कुल 3860.158 मिलियन अमरीकी डॉलर (32001.29 करोड़ रुपए) का विदेशी निवेश हुआ है। इसमें से 1559 मिलियन यूएस डॉलर की एफडीआई केवल सिंगापुर और यूके की है। यानी करीब 40 फीसदी निवेश इन दो देशों ने किया है। *(रा.प., 15.03.24)*

प्रदेश में लगेंगे पंप स्टोरेज प्लांट

राजस्थान में पानी से बिजली बनाने के लिए 20 हजार मेगावाट क्षमता के पम्प स्टोरेज सिस्टम लगाने की क्षमता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के इस आकलन के बाद राज्य सरकार प्रदेश को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है।

इसके लिए पहले चरण में टोंक, प्रतापगढ़, बूंदी, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही में आठ जगह चिन्हित की गई है। बूंदी और सिरोही में दो-दो लोकेशन पर काम होगा। इन आठ जगहों पर 7 हजार मेगावॉट क्षमता के स्टोरेज प्लांट लगाए जाएंगे। *(रा.प., 18.03.24)*

बीकानेर होगा सौर ऊर्जा में अव्वल

सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में बीकानेर विश्व में अव्वल बनेगा। यहां अभी 4324 मेगावॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। कुछ साल में बीकानेर 13964 मेगावॉट सौर ऊर्जा देने वाला विश्व का पहला जिला बन जाएगा। इसके लिए 38 हजार बीघा में 9640 मेगावॉट के सोलर प्लांट लगाने का काम चल रहा है। इसमें 5190 मेगावॉट की परियोजनाएं निजी क्षेत्र की हैं। इसके लिए 30 से ज्यादा कंपनियां रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं।

गौरतलब है कि बीकानेर में 365 दिन सूर्य की तेज रोशनी मिलती है और गर्मी में 45 डिग्री तापमान रहता है। एक मेगावॉट के प्लांट के लिए 4 बीघा जमीन चाहिए। यहां काफी बंजर भूमि भी है जिसका उपयोग सोलर प्लांट लगाने में होगा। इससे 15 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी जोधपुर पहले व बीकानेर दूसरे स्थान पर है। फलौदी के भड़ला में 2245 मेगावॉट का विश्व का सबसे बड़ा प्लांट है। *(दै.भा., 08.01.24)*

शांति और समृद्धि के लिए जल है जरूरी

संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जल दिवस के मौके पर जारी 'यूएन वर्ल्ड वॉटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2024' की थीम 'शांति और समृद्धि के लिए जल जरूरी' रखी गई है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया में बढ़ता जल संकट वैश्विक स्तर पर तनाव और अस्थिरता में बढ़ोतरी कर रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता दुनिया की शांति के लिए जरूरी है। दुनिया में फिलहाल करीब एक चौथाई मानवता यानी 2.2 अरब लोगों की पहुंच स्वच्छ पेयजल तक नहीं है और 3.5 अरब लोग स्वच्छ और सेहतमंद स्थितियों में जीवन यापन नहीं कर रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जल संकट का पहला शिकार बालिकाएं और महिलाएं होती है। क्योंकि परिवार के लिए पानी लाने और संग्रह करने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से उन्हीं पर है। रिपोर्ट में सुझाया गया है कि जल उपलब्धता के लिए सहभागिता को बढ़ाना और जल का सदुपयोग आवश्यक है। *(रा.प., 24.03.24)*

करना होगा जल संकट का सामना

एक शोध के मुताबिक 2050 तक विश्व में 3 अरब लोगों को नाइट्रोजन प्रदूषण के चलते स्वच्छ पेयजल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अनुमान है कि उच्च नाइट्रोजन प्रदूषण स्तर के कारण दक्षिणी चीन, मध्य यूरोप, उत्तरी अमरिका और अफ्रीका में छोटी नदी-घाटियां पानी की कमी वाले हॉटस्पॉट बन जाएंगी।

वैश्विक अध्ययन में जर्मनी के तीन और नीदरलैंड्स के दो संस्थानों के शोधकर्ताओं ने शोधपत्र में कहा है कि चार अरब लोग जिनमें से आधे चीन और भारत में हैं, हर साल कम से कम एक महीने गंभीर जल संकट का अनुभव करते हैं। नदियों में नाइट्रोजन प्रदूषण 2010 में पानी की कमी का बड़ा कारण था, 2050 तक स्थिति विकराल हो सकती है। शोधकर्ताओं ने पानी की मात्रा और गुणवत्ता की कमी होने का खतरा बताया है। *(रा.प., 08.02.24)*

पेयजल सप्लाई का समय निर्धारित

प्रदेश में जलदाय विभाग के डेढ़ करोड़ से ज्यादा पेयजल उपभोक्ता हैं। लेकिन प्रदेश में जयपुर सहित कई जिलों में हालात ऐसे है कि पेयजल सप्लाई का समय निर्धारित ही नहीं है। कभी तय समय से कई घंटें देरी या कभी पेयजल सप्लाई होती ही नहीं है। ऐसे में उपभोक्ता असमंजस की स्थिति में रहते हैं।

ऐसे हालात में उपभोक्ता अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए टैंकर से पानी भरवाते हैं। हाल ही विभाग की समीक्षा बैठक में सचिव डॉ. समित शर्मा ने इंजीनियरों को निर्देश दिया है कि जिस तरह से रेलवे में ट्रेनों का संचालन सही समय पर होता है उसी तरह पेयजल सप्लाई भी निर्धारित होनी चाहिए। देखा गया है जयपुर शहर के बाहरी इलाकों में नलकूपों से पानी पहुंचाया जाता है नलकूप खराब होने पर पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। ऐसे में क्षेत्र के उपभोक्ता पैसा खर्च कर पानी का टैंकर मंगाते हैं।

(रा.प., 16.01.24)

पानी के बिलों की वसूली पर चुप्पी

जयपुर शहर के उत्तर और दक्षिणी सर्कल के पानी के बिलों की बकाया 110 करोड़ से भी ज्यादा की राशि डूबत खाते में जाती दिख रही है। इस राशि को वसूलने में इंजीनियरों ने वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और अब एमनेस्टी स्कीम शुरू करने की पत्रावली सरकार को भेजी है।

मुख्य अभियंता (शहरी) आर.के.लुहाडिया अभी मुख्य अभियंता एनआरडब्लू भी हैं और अतिरिक्त पद की सुविधाएं भी ले रहे हैं, लेकिन राजस्व कैसे बढ़े इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जबकि उनको यह देखना भी जरूरी है कि पानी के बकाया बिलों की 110 करोड़ रुपए की वसूली के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए और फील्ड इंजीनियर वसूली क्यों नहीं कर रहे। मौजूदा वित्तीय वर्ष 31 मार्च को पूरा हो रहा है लेकिन वसूली को लेकर सभी ने चुप्पी साध रखी है।

(रा.प., 12.03.24)

गांवों तक पहुंचेगा पर्याप्त पेयजल

प्रत्येक गांव-ढाणी और कस्बे को पेयजल व सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जलापूर्ति के लिए राज्य सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है।

बूंदी जिले में जल जीवन मिशन के तहत रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना (विस्तार चम्बल भीलवाड़ा परियोजना) के लोकार्पण समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्वती कालीसिंध चम्बल परियोजना के मुख्य घटक नवनेरा बैराज का कार्य एक महीने में पूरा कर इसमें जल संग्रहण का कार्य शुरू हो जाएगा। *(रा.प., 08.03.24)*

प्रदेश की प्यासी धरा को मिलेगा पानी

काफी इंतजार के बाद पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईस्टर्न राजस्थान कैनाल लिंक प्रोजेक्ट (ईआरसीपी प्रोजेक्ट)पर राजस्थान, मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे मध्यप्रदेश और राजस्थान के 26 जिलों के 5 लाख 80 हजार से ज्यादा हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 30-40 साल तक लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा स्थाई रूप से मिल सकेगी।

एक और खुशखबरी यह है कि 30 साल पुराना विवाद भी सुलझ गया है। यमुना जल बंटवारा समझौता होने से राजस्थान के चुरू, सीकर, झुंझुनूं सहित अन्य जिलों को अब 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिल सकेगा। वहीं हरियाणा के भिवानी और हिसार जिलों को भी पानी मिल सकेगा। *(रा.प., 29.01.24, 18.02.24)*

फार्म पौण्ड बनाने पर मिलेगा अनुदान

प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर के कारण खेती-किसानी पर सीधा असर पड़ रहा है। सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए खेतों में फार्म पौण्ड बनाने पर सरकार किसानों को एक लाख 35 हजार रुपए तक का अनुदान देगी।

इन फार्म पौण्ड में सिंचाई के लिए बारिश का पानी संचय किया जा सकेगा। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमान्त किसानों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73 हजार 500 रुपए, कच्चे फार्म पौण्ड पर 90 प्रतिशत या एक लाख 35 हजार रुपए प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर अनुदान दिया जाता है।

(दै.भा., 28.02.24)

पीएमश्री विद्यालयों में लगेंगे शिविर

प्रदेश के पीएमश्री विद्यालयों को विकसित करने के साथ उनमें अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश के ऐसे 402 विद्यालयों में स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ परामर्श और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके लिए शिविर लगाए जाएंगे।

शिविरों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी इंडीकेटर्स की पहचान करके स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए जाएंगे। चिकित्सा विशेषज्ञों की ओर से हेल्थ स्क्रीनिंग के आधार पर उचित उपचार के लिए दवाएं और परामर्श दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सभी पीएमश्री विद्यालयों को स्वास्थ्य शिविरों के लिए फर्स्ट ऐड बॉक्स, वजन मापने की मशीन, थर्मामीटर, बीपी जांचने के लिए चिकित्सकीय उपकरण आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। जागरूकता के लिए स्वास्थ्य रैली, वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। *(रा.प., 31.01.24)*

मुख्यमंत्री-मा वाउचर योजना

गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए अब भटकना नहीं होगा। शिशु मृत्युदर में भी कमी लाई जा सकेगी। इसके लिए प्रदेश में सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मा-वाउचर) योजना लागू करने जा रही है। फिलहाल, पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे बारां, भरतपुर और फलौदी में लागू किया गया है।

इसमें गर्भवती को क्यू-आर कोड आधारित ई- वाउचर मिलेगा। इस वाउचर को देकर किसी भी निजी सेंटर में भी मुफ्त सोनोग्राफी कराई जा सकेगी। एसीएस (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा) शुभ्रा सिंह के अनुसार प्रदेश में जिन सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों में निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर दूसरी या तीसरी तिमाही में कम से कम एक जांच निःशुल्क करवाने के लिए यह योजना लाई गई है। अप्रैल से इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाना प्रस्तावित है। *(दै.भा., 16.03.24)*

सरे बाजार प्रसव मानवता की मौत

हाईकोर्ट ने प्रदेश में गर्भवती व प्रसूताओं के लिए केंद्र व राज्य सरकार की कई योजनाएं होने के बावजूद प्रसव के समय मां और शिशु की मौत पर चिंता जताई है। साथ ही इलाज के अभाव में सड़क पर प्रसव होने और जन्म लेने वाले जुडवां बच्चों की मौत के मामले में केंद्र व राज्य सरकार से पीड़ित महिला को चार लाख रुपए मुआवजा और 25 हजार रुपए अन्य खर्च के देने के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने यह निर्देश अलवर के खेड़ली में अप्रैल 2016 के दौरान सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साकर्मियों की कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता के चलते सरे बाजार सड़क पर प्रसूता को जुडवा बच्चों को जन्म के लिए मजबूर करने और बाद में इलाज नहीं मिलने से बच्चों की मौत होने को मानवता की मौत बताया। कोर्ट ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र व राज्य सरकार को संयुक्त उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया है।

(दै.भा. एवं रा.प., 22.02.24)

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद के नए भवन में पहले ही सत्र में महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। इससे लोकसभा और राज्य विधान मंडलों में कुल एक तिहाई सीटों पर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में लाने में गेमचेंजर सिद्ध होगा।

बिरला ने यह बातें संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधियों के लिए आयोजित पंचायत से संसद तक के उद्घाटन कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा भारत विकास में महिलाओं की भागीदारी व महिलाओं के नेतृत्व से आगे बढ़ रहा है। *(रा.प., 05.01.24)*

दुराचारी शिक्षकों की बन रही है सूची

प्रदेश की भजनलाल सरकार स्कूली बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार स्कूलों में छेड़छाड़-दुष्कर्म जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले शिक्षकों की सूची (सीक्रेट हिस्ट्री) तैयार कर रही है। कार्रवाई में ऐसे दुराचारी शिक्षकों की नौकरी जाएगी, साथ ही उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलेगा।

मालूम हो, प्रदेश में 5 साल में इस तरह की करीब 150 घटनाएं हो चुकी हैं। पता चला है कि संस्था प्रधानों से लेकर निदेशालय स्तर तक ऐसे शिक्षक-कर्मचारियों का डेटाबेस बन रहा है। इसमें खासकर छेड़छाड़-दुष्कर्म-कुकर्म जैसे मामले शामिल हैं। इसमें पुलिस रिकॉर्ड की भी मदद ली जा रही है। साथ ही इसके लिए पीड़ित, अभिभावक व पंचायतों से भी गोपनीय रिपोर्ट ली जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा हैं कि बेटियों के साथ छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। *(दै.भा., 15.02.24)*

ड्रोन से खेतों में बीज बोएंगी महिलाएं

प्रदेश में भी नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत महिला कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है। अब महिलाएं हाईटेक खेती में कदम रखेंगी। हाड़ौती में 104 महिलाओं का चयन 'नमो ड्रोन दीदी' योजना में किया गया है, जो खेतों में ड्रोन उड़ाएंगी और दवा स्प्रे से लेकर बीजों की बुआई भी करेंगी।

प्रदेश में इस योजना की शुरुआत कोटा जिले से होगी। इसमें 104 महिला स्वयं सहायता समूहों को खेती के लिए ड्रोन दिए जाएंगे। इस योजना के लिए प्रदेश में खेती का प्रशिक्षण देने के लिए पांच कंपनियों को जिम्मा दिया गया है। इस योजना के जरिए महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जाएगा। इससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, दक्षता और रोजगार में बढ़ोतरी होगी।

(रा.प., 10.03.24)

बढ़ रही वाहनों की संख्या, साथ ही बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं

शहर में लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। राजधानी जयपुर में हर साल सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में 100 से ज्यादा की वृद्धि हो रही है। वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 625 थी। उसके बाद 2022 में 766 और वर्ष 2023 में 844 पहुंच गई। वर्ष 2023 में 2914 सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज हुई है। जिनमें 2332 घायल और 844 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा आधे से ज्यादा वो हादसे हैं,जिनके संबंध में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है।

शहर में लगातार बड़ रहे हादसों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हादसे बढ़ने की वजह रोड इंजीनियरिंग की कमी के साथ-साथ अस्थाई अतिक्रमण और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का अभाव है। यातायात पुलिस के अनुसार शहर में ऐसे कई प्वाइंट हैं, जहां पर बेसिक सुधार करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। इन प्वाइंटों का सर्वे करवाया जा रहा है, जिनकी रिपोर्ट कर संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। *(दै.भा., 16.01.24)*

हादसों में ज्यादा जान गंवा रहे युवा

जागरूकता की कमी और लापरवाही के चलते राजस्थान में बीते वर्ष सड़क हादसों में सबसे अधिक युवाओं ने जान गंवाई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग इस वर्ष युवाओं को फोकस में लेकर काम कर रहा है। सड़क हादसे रोकने के लिए एम्स दिल्ली की सहभागिता से विभाग ने कवायद शुरू की है।

इसके तहत राज्य के कॉलेजों में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर परिवहन विभाग और एम्स की ओर से गुड सेमेरिटन (दुर्घटना में घायल की जान बचाने वाले) तैयार किए जा रहे हैं। जयपुर में दो शिक्षण संस्थानों में लाइफ सपोर्ट सिस्टम सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी के तहत करीब 25 लाख रुपए का फंड भी जारी किया है। शिक्षकों को ट्रेनर के रूप में तैयार किया जा रहा है। ये शिक्षक फिर छात्रों को प्रशिक्षण देंगे। विभाग का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में गुड सेमेरिटन तैयार किए जाएं। *(रा.प., 20.02.24)*

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग की ओर से एक अप्रैल से ई-आरसी और ई-लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसको लेकर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रथम कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा वीसी के माध्यम से जुड़ी थीं। इसमें विभाग की ओर से शुरू की गई नई व्यवस्था की जानकारी साझा की गई।

आरटीओ प्रथम राजेश कुमार चौहान ने बताया कि एक महीने तक शहर के परिवहन कार्यालयों में ई-आरसी और ई-लाइसेंस के फ्री प्रिंट निकाल कर दिए जाएंगे। एआरटीओ प्रकाश टहलियानी ने बताया कि अब सड़क पर नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस पर कार्रवाई ई-चालान पोर्टल के जरिए की जाएगी। इसके बाद अगर लाइसेंस निलंबित के लिए भी भेजा जाएगा तो परिवहन अधिकारी पोर्टल पर ऑनलाइन ही कार्रवाई करेंगे। इसके लिए यातायात पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नए वाहन खरीद के दौरान टोहास की एक बुकलेट प्रत्येक व्यक्ति को खरीदने की जरूरत होगी। इस बुकलेट के जरिए ड्राइविंग के नियम समझाए जाएंगे। *(रा.प., 22.03.24)*

कैसे हो सड़क पर सुरक्षा?

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग और यातायात पुलिस की ओर से हर साल सड़क सुरक्षा माह का आयोजन होता है। जागरूकता के बाद भी हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही है। हर साल हादसों और मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है।

राजस्थान में साल 2023 में हुए सड़क हादसों की रिपोर्ट जारी की गई है। साल 2022 की तुलना में 2023 में हादसों, घायलों और मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। सड़क हादसों में जहां पांच फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, घायलों की संख्या में 3 फीसदी का इजाफा हुआ है। इसी प्रकार 6 फीसदी मौतों का ग्राफ भी बढ़ा है। प्रदेश में कुल मौतों की संख्या में भले ही बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 19 जिलों में मौतों का आंकड़ा कम हुआ है। इसके अलावा 16 जिलों में हादसे कम हुए हैं। वहीं 19 जिलों में घायलों की संख्या में कमी आई है। साल 2024 में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से फिर सड़क सुरक्षा माह आयोजित होगा। *(रा.प., 15.01.24)*

ग्रामीण सड़कों का होगा नवीनीकरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश की 883 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण होगा। इस योजना के तहत 297 सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए 120 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति जारी हुई है। पीडब्लूडी द्वारा इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान में पीएम ग्राम सड़क योजना में उत्कृष्ट एवं गुणात्मक कार्य के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राशि जारी की गई थी। इस राशि से ग्रामीण सड़कों का विकास होगा जिससे ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। *(दै.भा., 23.02.24)*

चौराहों पर से पुलिसकर्मी नदारद

सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जयपुर की बड़ी कॉलोनियों में स्थित चौराहों और विभिन्न पाइंट पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तो लगाई जाती है, लेकिन देखने में आ रहा है कि वे ज्यादातर समय अपनी ड्यूटी से नदारद रहते हैं।

इसके चलते शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर के अलावा न्यू सांगानेर रोड, जगतपुरा का सात नंबर चौराहा और वैशाली नगर जैसे मुख्य जगहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी होने के बावजूद मौजूद नहीं रहने से वाहन चालक मनमाने तरीके से निकलते है और यातायात नियमों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। *(दै.भा., 11.03.24)*

उपभोक्ता फैसले

अस्पताल को भारी पड़ा ऑपरेशन में लापरवाही बरतना

जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग (द्वितीय) में चाकसू निवासी लाला राम ने घीया अस्पताल व प्रबंधन के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि उसने घीया अस्पताल में अपनी पत्नी सायर को डिलेवरी के लिए भर्ती कराया था। इसके लिए 14 हजार रुपए भी जमा कराए थे। लेकिन अस्पताल ने बिना सिजेरियन डिलेवरी की जरूरत के ही ऑपरेशन कर दिया और इसमें गंभीर लापरवाही बरतते हुए बच्चेदानी को काट दिया। इससे काफी रक्तस्राव हुआ और हालत गंभीर हो गई। अस्पताल ने परिजनों से इसे छिपाए रखा और हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे महिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। जहां रक्तस्राव के चलते उसकी पत्नी की मौत हो गई। मामले की सुनवाई पर अस्पताल की ओर से दलील दी गई कि परिवादी आपातकालीन परिस्थिति में अपनी पत्नी को लेकर आया था और उन्होंने सही व उचित इलाज किया था।

उपभोक्ता आयोग ने माना कि अस्पताल ने गंभीर लापरवाही बरतते हुए बच्चेदानी को चीरा लगाया। इससे अत्यधिक रक्तस्राव के चलते प्रसूता की मौत हुई है। आयोग ने घीया अस्पताल और प्रबंधन को दोषी मानते हुए आदेश दिया कि वह लाला राम को 15 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि नौ फीसदी ब्याज सहित दें। साथ ही परिवाद खर्च के दस हजार रुपए अलग से अदा करें। *(दै.भा., 14.02.24)*

ऑपरेशन में बरती लापरवाही, अस्पताल पर लगा जुर्माना

जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग (द्वितीय) में कृष्ण अवतार मालाणी ने सीकर रोड स्थित मणिपाल अस्पताल के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि 8 फरवरी 2022 को पेट में दर्द होने पर हॉस्पिटल में डॉक्टर दिव्य रतन धवन को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि उनकी बांयी ओर किड़नी के यूरेटर में पथरी है। दूरबीन के जरिए उसका सामान्य ऑपरेशन कर पथरी को निकाल दिया जाएगा। कोई परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद उनका यूरीन बन्द हो गया। दोबारा दिखाने पर ट्यूब के जरिए यूरीन निकाल दिया और दवा देकर डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद उनके यूरीन में दर्द व ब्लडिंग होने लगा। दुबारा भर्ती होने पर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। तब दूसरी जगह दिखाया तो पता चला कि किडनी में छेद हो गया है। इसके इलाज में 3.10 लाख रुपए खर्च हुआ।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से मरीज की किडनी में छेद करने को गंभीर सेवा दोष माना। आयोग ने मणिपाल हॉस्पिटल पर 15.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही निर्देश दिया कि वह मरीज के इलाज में खर्च हुए 3.10 लाख रुपए भी उसे 9 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित वापस लौटाए।

(दै.भा., 16.03.24)

नया नियमः प्रति इकाई बिक्री मूल्य लिखना होगा
डिब्बाबंद उत्पादों पर उत्पादन की तारीख लिखना अनिवार्य

अब पैकेज्ड प्रोडक्ट यानी डिब्बाबंद उत्पादों पर उत्पादन की तारीख और उसकी प्रति यूनिट कीमत लिखी हुई मिलेगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि सभी डिब्बाबंद जिंसों पर मैन्यूफैक्चरिंग की तारीख और प्रति इकाई बिक्री मूल्य 1 जनवरी 2024 से लिखना अनिवार्य हो गया है। पहले कंपनियों को डिब्बाबंद उत्पादों पर उत्पादन की तारीख या आयात या पैकेजिंग की तारीख प्रकाशित करने का विकल्प था।

रोहित कुमार ने कहा कि इन नियमों के बाद ग्राहक सोच-विचार कर वस्तु खरीद सकेंगे। मैन्यूफैक्चरिंग की तारीख प्रकाशित होने से ग्राहकों को यह जानने में मदद मिलेगी कि पैक की गई वस्तु कितनी पुरानी है। उदाहरण के लिए 2.5 किलोग्राम के पैकेटबंद गेहूं के आटे में एमआरपी के साथ प्रति किलो बिक्री मूल्य लिखना होगा। वहीं एक किलो से कम मात्रा वाले उत्पाद के पैकेट पर एमआरपी के साथ प्रति ग्राम बिक्री मूल्य भी लिखना होगा।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार डिब्बाबंद उत्पादों पर कंपनियों को अब उत्पाद की 'प्रति यूनिट बिक्री मूल्य' के साथ 'उत्पादन की तारीख' प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। ताकि उपभोक्ता एक सूचित निर्णय ले सके और करों का भुगतान करने के बाद उत्पाद खरीद सके।

ब्राजील की अंतरराष्ट्रीय सलाहकार परिषद् में सदस्य बने महता

'कट्स' इंटरनेशनल के महामंत्री प्रदीप महता को टी20 ब्राजील की अंतरराष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा 'कट्स' इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक बिपुल चट्टोपाध्याय को टी20 ब्राजील के टास्क फोर्स 4 के उप-विषयों में से एक का सह-अध्यक्ष बनाया है। यह टास्क फोर्स सतत् व समावेशी विकास के लिए व्यापार-निवेश से संबंधित मुद्दों को सुलझाएगी।

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैरोबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)